THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, reply by the hon. Home Minister and the Deputy Prime Minister, Shri L. K. Advani, to the Short Duration Discussion.

SHORT DURATION DISCUSSION

The present situation in Jammu and Kashmir with particular reference to recent massacre in Kasim Nagar on July 13, 2002 and the failure of the Goverment in this regard

उपप्रधान मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): उपसभापति महोदया, जम्मू में कासिमनगर में जो दर्दनाक घटना हुई, उसकी पृष्ठभूमि में पिछले सप्ताह दूसरे सदन में विस्तृत चर्चा हुई और कल इस सदन में भी हमने उसी विषय पर चर्चा की । मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर इन दोनों चर्चाओं को सुनेगा और इनका विश्लेषण करेगा तो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में, आतंकवाद के संकट के बारे में, थोड़े-बहुत मतभेद भले ही हों लेकिन कुल मिलाकर दोनों सदन एकमत हैं । इसलिए सबसे पहले कल जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और विशेषकर मैं विपक्ष के नेता डा. मनमोहन सिंह जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा को आरंभ किया और इस चर्चा का लहज़ा कैसा होना चाहिए, इसमें क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इस बात को एक प्रकार से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया । कई सदस्यों ने आलोचना भी की । आलोचना होना स्वाभाविक है लेकिन कुल मिलाकर सारी डिबेट का अंडरटोन कंस्ट्रक्टिव था ।

महोदया, मैं यहां हरेक सदस्य का नाम तो नहीं ले सकता लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल किसी भी सदस्य ने कोई ऐसी बात कही हो कि जिस पर मैं आपत्ति कर सकूं । उनको यह कहने का अधिकार है कि आपने अमुक बात की थी लेकिन अभी भी क्रॉस बॉर्डर टैररिज्म जारी है, क्यों जारी है जब कि आपको हमने पूरा अधिकार दिया था और हमने प्रस्ताव पारित करके कहा था कि आप जो करना चाहें, करिए ।

महोदया, संसद में हुई इस चर्चा से जिस प्रकार का संदेश देश को जाना चाहिए, हमारे शत्रुओं को जाना चाहिए, विदेशों को जाना चाहिए या सरकार को उसमें से जो बोध लेना चाहिए, वे सभी बातें कल की चर्चा में उभरकर सामने आईं, यह मैं मानता हूं । और इस कारण कल की चर्चा बहुत सार्थक रही। जेठमलानीजी ने बड़े विस्तार से उन्होंने जो प्रयत्न किए थे उसका जिक्र किया। कुछ लोगों ने कहा कि यह आफिशियल है या अन-आफिशियल है मैं उस समय अपने मार्क्सवादी नेता से कहने वाला था कि आप भी इस दिशा में कुछ प्रयत्न करें तो मैं तो स्वागत करुंगा। आपको अधिकार हो कि न हो यह सवाल नहीं है, सवाल यह है कि इस समय हर एक व्यक्ति चिंतित है कि क्रौस बोर्डर टेरेरिज्म बंद होना चाहिए, जम्मू कश्मीर की जो हमारी आंतरिक समस्याएं हैं वह हल होनी चाहिए। मैं अगर 6-7 विषयों को सार के रूप में सदन के सामने रखने की कोशिश करुं, जिस पर सदस्यों ने चिंता प्रगट की। यह चिंता तो सब की थी कि क्रौस बोर्डर टेरेरिज्म पाकिस्तान द्वारा जारी है, लगातार जारी है। उसमें कोई कहेगा कि इंफिल्ट्रेशन में थोड़ी कमी आई है, कोई कहेगा कि कमी नहीं आई है, कोई विदेशी दावा करेगा

कि इंफिल्ट्रेशन बंद हो गया है। मेरे पास अभी अभी आज प्रातःकाल ही यह सूचना मुझे प्राप्त हुई है कि कल रात्रि को राजौरी नगर के पास में एक जोइंट आपरेशन लांच हुआ आर्मी द्वारा और उसमें चार मिलिटेंटस मारे गए और आर्मी का एक केप्टेन मारा गया। यह बहुत बड़ा षड़यंत्र था जिसको विफल किया गया और यह कल की ही बात है।

श्री गुलाम नबी आजाद (जम्मू और कश्मीर): अभी भी जारी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : रात भर चली है और अभी शांत हुआ है लगभग। जो लेटेस्ट है वह अभी शांत हुआ है। लेकिन मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि यह एक कंटीन्यूइंग ए प्रोब्लम है और इसीलिए यह चिंता सबकी स्वाभाविक थी कि क्रौस बोर्डर टेरेरिज्म जारी है। कोई इस गलतफहमी में न रहे कि जारी नहीं है। इस मामले में डा. मनमोहन सिंह जी का यह कहना सही था कि लगता है कि अमेरिका के या पश्चिम के देशों को जो असेस्मेंट हैं इस विषय में और भारत के जो असेसमेंट हैं उसमें फर्क है, है फर्क और इसमें कोई संदेह नहीं और हमारा जो फर्क है वह जब भी कभी उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है साफ उनसे कहते हैं। मैंने तो उनसे यह कहा कि मैं समझने में असमर्थ हूं कि हम जब कहते हैं कि क्रौस बोर्डर टेरोरिज्म बंद होना चाहिए तो आप अगर पाकिस्तान से बात करते हैं केवल इस बात पर बल देते हैं कि इंफिल्ट्रेशन बंद हो और उन्होंने वचन दिया है कि हम इंफिल्ट्रेशन बंद कर देंगे। मैंने कहा कि हमारे विवेचन के अनुसार क्रौस बोर्डर टेरोरिज्म इसका एसियंशयल फीचर है A State adopting terrorism as an instrument of its policy. उसका एसियंशयल फीचर है और अभी तक इस बात का तनिक भर भी लक्षण नहीं मिला है कि पाकिस्तान इसको नीति के तौर पर जो उन्होंने अपनाया है 1971 के युद्ध के बाद 1972 से लेकर के मैं मानता हूं कि उसका परित्याग करने को तैयार है। क्योंकि उसके लिए उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप किया है। आइ.एस.आई. को उसकी रेस्पांसिबिलिटी दी है कि इस क्रौस बोर्डर टेरेरिज्म की हमारी योजना को, हमारी रणनीति को सफल करने के लिए तुम हमारे प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट हो, करिए। हथियार जो किसी समय उनको मिले, उसका उपयोग होता है आज भी होता है। इसलिए डा0 साहब की यह बात सही है कि हमारा और उनका असेस्मेंट अलग है। उस असेस्मेंट में मैं यह भी मानता हूं कि हरएक देश अपने-अपने जो उसके नेशनल इंटरेस्ट हैं, उसके हिसाब से अपनी नीति बनाता है। पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का रवैय्या हमारी इच्छा के अनुसार हो यह तो कोई जरूरी नहीं, जैसे उनकी इच्छा के अनुसार हमारा रवैय्या हो, यह जरूरी नहीं। तीसरी बात, आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि Let there be no excessive reliance on coercive diplomacy. सही बात है। मैं पहले भी इस सदन में कह चुका हूं कि पाकिस्तान द्वारा क्रौस बोर्डर टेरेरिज्म हमारी समस्या है यह विश्व की समस्या नहीं है। विश्व कहता है कि हमारी समस्या है, टेरेरिज्म कहीं भी हो हमारी समस्या है। 11 सितम्बर के बाद उन्होंने कई ऐसी घोषणाएं की हैं। लेकिन ऐसे मौके बहुत आए जब अमेरिका के नेताओं को भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि कभी-कभी लगता है आपकी टेरेरिज्म के बारे में जो चिंता है, वह सीमित है और वह 11 सितम्बर की घटनाओं के बारे में है। 11 सितम्बर की जो घटनाएं हुईं, उसके प्रति आपकी रिप्रेज़ल है समझ में आता है, बाकी दुनिया भर में जहां पर भी टेरेरिज्म होगा, वह हमारे लिए शत्रु है और हम उसको मिटाने में अग्रणी होंगे, यह जो आपके वचन हैं, ये कम से कम हमको आश्वस्त नहीं करते हैं। क्योंकि हमने उसके लक्षण अभी तक नहीं देखे हैं और मैंने इस बात पर और बल दिया है, लगातार जब भी मिलते हैं, उनके प्रवक्ताओं से मिलने

का मौका आया है कि आपको इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक लोकतंत्रीय देश है, पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान में वहां का नेता, वहां का राजनेता जो कहता है, उसको आप पाकिस्तान मान सकते हैं। लेकिन यहां पर भारत सरकार क्या कहती है इसका महत्व है, विपक्षी दल क्या कहते हैं इसका महत्व है और इससे ज्यादा महत्व इस बात का है कि इस देश का जो आम नागरिक है वह क्या सोचता है, वह क्या कहता है। इन दिनों में मुझे उनको कहने का अवसर मिला कि हम यह मानते हैं कि जब शीत काल का समय था, शीत युद्ध का समय था, शीत युद्ध के समय में सर्वसाधारण नागरिक यह मानता था कि यदि भारत का दुनिया में कोई दोस्त है तो वह रूस है, यूएसएसआर है और हमारा जो निकट का शत्रु है, जिसने तीन-तीन युद्ध हमारे साथ किए, यह तब की बात है, उस पाकिस्तान का कोई दोस्त है तो अमेरिका है, वाशिंगटन है, यह सर्वसाधारण नागरिक भारत का मानता रहा है। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद अपेक्षा थी कि इस स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आयेगा और दुनिया का जो सबसे सशक्त लोकतंत्र है, वह लोकतंत्रीय निष्ठा के आधार पर इस बात का विशेष प्रयत्न करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल लोकतंत्र भारत का है, उसके साथ सबसे अच्छे संबंध बनेंगे। शीत युद्ध के समय के नहीं, इसमें समय लगेगा। लेकिन मैं यह मानता हूं कि इन पिछले कुछ सालों में परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन को जब उनके नेता आए, उनके राष्ट्रपति यहां पर आये तब भी हमने देखा, उनकी बातें सुनीं। बाद में जो कुछ होता रहा है उसके आधार पर भी परिवर्तन आया है। मुझे कभी-कभी लगता है कि कोल्डवार के समय के जो एटीट्यूड हैं, वह कहीं-कहीं फ्रोज़न हो गए हैं कुछ सैक्शन्स में, कहीं-कहीं जनता में भी विगत दिनों में अमेरिका के जितने प्रतिनिधि मुझे मिले हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूं रहा हूं कि जब आप बड़ी तारीफ करते हो एक देश की, जिसके कारण हमारे यहां पर आतंकवाद आया है इसको भारत का सर्वसाधारण नागरिक मानता है। आतंकवाद के कारण पिछले 15 सालों में सात हजार बेकसूर लोगों ने जानें गवाईं हैं, तो जिस पाकिस्तान के कारण गंवाई है, उस पाकिस्तान की इतनी प्रशंसा करने वाला अमेरिका क्या वह उस शीत युद्ध के काल में वापस पहुंच रहा है, यह आशंका उनके दिलों में पैदा होती है। मैंने कहा कि मैं नहीं मानता, सरकार नहीं मानती है। सरकार मानती है कि उस काल से आप कुछ हटे हैं, आगे बढ़े हैं, भारत के साथ निकटता बढ़ी है, इस बात का भी अहसास बढ़ा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है।

यद्यपि एक समय था जब कोई दूसरा लोकतंत्रीय देश नहीं होता था तो उनके बारे में बहुत सारी रिजर्वेशन्स होती थीं। लगता है कि आपने पाकिस्तान के बारे में छोड़ दी, कोई बात नहीं, आपकी अपनी रणनीति है, आपका अपने इंटरेस्ट का तकाज़ा होगा कि कुछ करें। यह भी कहा गया कि भाई इस बार के चुनाव जो होने वाले हैं वह फ्री एंड फेयर होने चाहिए। मैं समझता हूं कि यह चिंता बिल्कुल सही है, स्वाभाविक है और इसीलिए आज यहां पर आने से पहले एक बार फिर मैंने जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री डा0 फारूख अबदुल्ला से बात की और मैंने उनसे कहा कि कल जितने लोग बोले, उनमें कई बातें उन्होंने कही होंगी। लेकिन शायद ही कोई सदस्य इस बात को बल देने से चूक गया होगा कि आने वाले विधान सभा चुनाव पूर्णतः निष्पक्ष हों, प्रमाणिक हों। मुक्त रूप से हों, उसमें आम नागरिक को सुरक्षा प्राप्त हो और अधिक से अधिक लोग उसमें भाग लें, इस दिशा में प्रयत्न होना चाहिए । उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल सहमत हूं और आप मेरी तरफ से, मेरी सरकार की तरफ से, प्रदेश की तरफ से लोगों को यह आश्वासन दे सकते हैं कि कोई भी भारत का नागरिक या भारत में बसने वाला, उन्होंने यहां तक कहा कि ऐम्बेसिज़ के भी जो ऐम्बेसेडर्स हैं या कोई भी एन.जी.ओ., कोई भी नॉन गवर्नमेंटल

ऑरग्नाइज़ेशन अगर यहां आकर चुनाव को देखना चाहे, परीक्षण करना चाहे, मॉनिटर करना चाहे तो मेरी तरफ से उनको पूरी छूट है, मैं उनका स्वागत करूंगा, वे यहां आएं, आकर देखें । उन्होंने मुझे यह सब कहा और मैं आपके सामने इस बात को कहता हूं । लेकिन मैं अपनी तरफ से इलैक्शन कमीशन को जरूर इस बात पर बल दूंगा कि इलैक्शन कमीशन इस दिशा में जो भी कुछ कर सके और जो भी कुछ करना संभव हो so that elections in Jammu and Kashmir are not only free and fair, but they also seem to be free and fair. दिखना भी चाहिए कि वह मुक्त हैं, वह निष्पक्ष हैं, इस बात की वह व्यवस्था करे । इस दृष्टि से अगर आपके भी कोई सुझाव हैं तो उनका मैं स्वागत करूंगा । अलबत्ता मैं इस मत का जरूर हूं कि इस मामले में कोई अगर यह कहे कि हम विदेशी लोगों को बुलाएं तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि कोई विदेशी आकर यहां इलैक्शंस को मॉनिटर करे, मैं उससे सहमत नहीं हूं - नो सर्टीफिकेशन । क्योंकि मैं मानता हूं कि जम्मू-कश्मीर हमारी समस्या है । जम्मू-कश्मीर 1947 से भारत का अभिन्न अंग है और उससे पहले तो था ही लेकिन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तब हिन्दुस्तान में 550 या 560 ऐसे रजवाड़े थे, जिन रजवाड़ों को उस समय अंग्रेज सरकार ने यह छूट दी कि आप जिसके साथ जाना चाहें, जा सकते हैं । आप भारत के साथ जाना चाहें तो भारत के साथ जाएं और अगर आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहें तो पाकिस्तान के साथ जाएं । यह छूट उन्होंने दी । वहां के महाराजा ने ऐक्सीड किया। उसकी लम्बी-चौड़ी चर्चा कल भी थोड़ी-बहुत हुई थी । महाराजा के ऐक्सीड करने के बाद भी भारत सरकार ने कहा कि हम महाराजा के ऐक्सैशन मात्र से संतुष्ट नहीं हैं । हम तो चाहेंगे कि वहां की प्रतिनिधि संस्था, वहां की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस बात की पुष्टि करे और इतना ही नहीं, जब तक वहां की कॉन्स्टीट्यूऐंट असैम्बली ने उसकी पुष्टि नहीं की, हमारा समाधान नहीं हुआ । वहां की कॉन्स्टीट्यूऐंट असैम्बली ने पुष्टि की कि हम भारत के साथ हैं । हिन्दुस्तान के बहुत सारे रजवाड़े हैं, वह रजवाड़े हमारे साथ आए, कुछ रजवाड़ों के बारे में तो वहां के नवाब ने शायद कहा होगा मैं पाकिस्तान जाता हूं, जूनागढ़ के साथ ऐसा ही हुआ लेकिन वह हमारे साथ आए, हमारे साथ मिले । जम्मू-कश्मीर के बारे में शुरू से लेकर अगर हमारे यहां पर बहुत चिंता रही तो उसका कारण है कि बाकी भारत का विभाजन, हिन्दुओं का बहुमत कहां है, मुसलमानों का बहुमत कहां है, इस आधार पर हुआ । रजवाड़ों पर यह लागू नहीं था और यह लागू न होते हुए भी सबको यह जानकारी थी कि जम्मू-कश्मीर राज्य में मुस्लिम बहुमत है और मुस्लिम बहुमत के महाराजा ने अगर ऐक्सीड किया तो प्रधान मंत्री ने कहा कि उनके ऐक्सीड करने से मुझे संतोष नहीं है, चाहे लीगली, कॉन्स्टीट्यूशनली यह बिल्कुल भारत का हिस्सा हो गया लेकिन कुल-मिलाकर हमको पॉलिटिकल स्ट्रेंथ तब मिलेगी, जब वहां की प्रतिनिधि संस्था, वहां के प्रतिनिधि संगठन अपने को ऐक्सीड करने के साथ जोड़ेंगे, और उन्होंने जोड़ा । इससे भी ज्यादा चिंता इस बात की थी । 1951 में यहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें पंडित नेहरू बोले तब नेहरू जी ने उस समय कहा "Kashmir has become a living symbol of that non-communal and secular State which will have no truck with the two-nation theory on which Pakistan has based itself." It is a quotation of Pt. Nehru. उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह इस बात पर है, जम्मू-कश्मीर के हमारे साथ आने में क्योंकि टू-नेशन थ्योरी को अगर कोई झुठलाता है तो जम्मू-कश्मीर का यह निर्णय झुठलाता है । यह बात अलग है कि आगे चलकर बंगलादेश ने भी उसको झुठला दिया । लेकिन मैं मानता हूं कि तब से लेकर Pakistan has failed to reconcile with India as a

secular State.इंडिया का जो यह स्वरूप है कि जिसमें इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम जनसंख्या होते हुए भी, इंडोनेशिया को छोड़ कर दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या हो । उसके बावजूद यहां पर सेक्युलरिज्म है, ईक्वेलिटी है, कंस्टीट्यूशन में लिखा है, आचरण में है, व्यवहार में है । मुस्लिम समाज के लोग ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, आर्मी के बन सकते हैं । ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खटकती हैं, हज़म नहीं होतीं पाकिस्तान को और तब से पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर को किसी न किसी प्रकार से अपने साथ जोड़ने के लिए लगा हुआ है । दूसरा कोई तरीका नहीं निकला तो.... मैं मानता हूं कि दो फेजेज़ रहे हैं, पहले 25 साल, 1947 से लेकर 1972, फर्स्ट फेज़ । यह कन्फ्रंटेशन जो है, वह ओपन्ड वार्स में प्रकट हुआ, ओवर्ट वार्स । 1947 में पहला युद्ध, 1965 में दूसरा युद्ध, 1971 में तीसरा युद्ध । फिर उसके बाद से लेकर, 1972 से लेकर 2002 तक, ये जो तीस साल बीते हैं, ये तीस साल ओवर्ट वार नहीं हुए । कोई कह सकता है कारगिल को लेकिन कारगिल को भी मैं उस कोवर्ट वार का हिस्सा मानता हूं जो कि उन्होंने तीस साल तक चलाया है, जिन तीस सालों में से पहले दस साल उन्होंने तैयारी की, preparation किया । पिटे हुए थे, 1971 में ऐसी पिटाई हुई थी कि जिसमें से निकलने के लिए और सारी रणनीति को बदलने के लिए उन्हें दस साल लगे । लेकिन 1980 से लेकर या 1982 से लेकर लगातार आज तक, बीस सालों तक कोवर्ट वार चलता रहा । इसलिए कभी-कभी यह हो जाता है । फिर यह हो गया, फिर कालूचक हो गया, फिर यह हो गया । तो आप क्या कर रहे हैं ? कोई कह देता है, जनेश्वर जी जैसे मित्र हैं जो कह देते हैं कि त्याग-पत्र दे देना चाहिए । बहुत सरल है । मुझे भी कभी-कभी वेदना होती है, व्यथा होती है अगर कुछ होता है और पहला रीएक्शन मेरा भी वही होता है जो आपने कहा लेकिन साथ-साथ जब मैं यह सोचता हूं कि यह कोई आज की बात नहीं है। This is not something that has started today. This is not something that has started in 1998 after we came to power. But this is a long story. It is a continuing war और उस वार में कभी हार कभी जीत, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, लीनियर वार नहीं होता है, वार तो चलता है । संकल्प चाहिए कि इस वार में भी वैसी ही विजय प्राप्त करेंगे जैसी 1971 में प्राप्त की थी, वह संकल्प चाहिए और कल की चर्चा उस संकल्प का परिचायक है । कल की चर्चा इस संकल्प का परिचायक है कि इस देश में यह संकल्प है कि हम हर सूरत में इस कोवर्ट वार, इस प्रॉक्सी वार, इस परोक्षा युद्ध में भी विजय प्राप्त करेंगे। हां, उसके लिए आपने जो कुछ कहा वह बिलकुल सही है कि We cannot depend on other countries to take our bones out of the fire. No. मैं तो मानता हूं कि कश्मीर की समस्या मूलतः हमारी इंटरनल समस्या है । 1947 में जब हमारे ऊपर हमला हुआ पाकिस्तान का, It became a bi-lateral issue और पिछले कुछ सालों में जब से टेररिज्म आया है और टेररिज्म को as an instrument of State Policy उन्होंने बनाया है, हमने दुनिया भर में इस बात कोशिश की है कि सारी दुनिया इस बात के प्रति जागरूक हो कि टेररिज्म अगर कोई भी स्टेट अपनी स्टेट पॉलिसी के रूप में अपनाता है तो सारे ग्लोब को उसकी चिंता करनी चाहिए । It is only this aspect of cross-border terrorism which may give it an international dimension. अंतर्राष्ट्रीय आयाम अगर जम्मू-कश्मीर की बात को कोई बात देती है तो it is cross border terrorism और इसीलिए सरकार ने पूरी कोशिश की है कि जब भी विदेशी आएं, अमेरिकी आएं, यू.के. के लोग आएं, जम्मू-कश्मीर की बात करें तो जम्मू-कश्मीर के बारे में बात करते हुए हम उनसे बातचीत पूरी की पूरी इस cross-

border terrorism as an instrument of State Policy, Infrastructure of cross-border terrorism, उसकी चर्चा करें । जम्मू-कश्मीर का हल क्या होगा, डिवॉल्यूशन ऑफ पावर्स कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हमारी इंटरनल हैं, इसमें उनका कोई लेना-देना नहीं है, हम उसकी बातचीत करेंगे । उसी प्रकार से लोगों ने कहा कि ...(**व्यवधान**)... मैं महासंघ का जिक्र करुंगा, ट्राइ फरकेशन के बारे में सब कह रहा हूं। शायद ही कोई हो जिसने ट्राइ फरकेशन के बारे में न कहा हो। कुलदीप नयैर ने ट्राइ फरकेशन की तो बड़ी आलोचना की, लेकिन इस बात को नोट भी नहीं किया कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, किसी ने भी कहा हो ट्राइ फरकेशन के पक्ष में हमने तुरंत एक दिन भी जाने नहीं दिया, उसी दिन कहा कि गलत बात है, हम नहीं मानते। कारण यह है, समझना चाहिए ...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please let him reply. No interruptions.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं जम्मू-कश्मीर और जम्मू-कश्मीर की स्थिति और वहां की समस्याओं से, जब से राजनीति में आया, 1951 में तब से लेकर अब तक जुड़ा हुआ हूं। इस नाते कि हमारे जनसंघ के संस्थापक डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर को अपना प्रमुख इश्यु बनाया, प्रमुख मुद्दा बनाया। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू -कश्मीर की एकता के लिए, उसकी इंटीग्रेशन के लिए संघर्ष किया । उस समय स्थिति यह थी कि जम्मू-कश्मीर में जाने के लिए हमको परमिट लेना पड़ता था। उन्होंने कहा कि मैं वहां बिना परमिट जाऊंगा और बिना परमिट लिए वे वहां गए। पठान कोट के आधे पुल पर, भारत सरकार भी चाहती तो उन्हें पकड़ सकती थी क्योंकि वे बिना परमिट के जा रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें नहीं पकड़ा। हो सकता है भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर की सरकार से बात की हो कि जो करना है, आप करिए और जम्मू-कश्मीर की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। 1953 में कारावास में, रहस्यपूर्ण परिस्थियों में डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। तब से लेकर वह हमारे मन के ऊपर बोझ रहा है कि इतना बड़ा बलिदान हुआ, इतना बड़ा त्याग हो गया। यह ठीक है उसके तुरन्त बाद कुछ बातें हुई हैं जिनके अनुसार परमिट सिस्टम खत्म हो गया, और एक के बाद एक कई कदम उठाए गए इंटीग्रेशन के। जिससे वहां इलैक्शन कमीशन का प्रभाव बढ़ गया, कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल का भी प्रभाव बढ़ गया, राष्ट्रपति शासन की भी गुंजाइश हो गई। अनेक बातें हो गई इंटीग्रेशन की डायरेक्शन में आफ्टर दैट ट्रेजिडी। इसीलिए मैं इस बात को कहूंगा कि जिस समय हमारे सामने यह प्रस्ताव आया, उसका नाम एटोनोमी लिया जाता है। लेकिन अगर आप पूरे दस्तावेज पढ़ें तो उसमें कौन-कौन सी बातों में स्वायत्तता चाहिए, इसका उल्लेख नहीं है। 1953 से पहले जो पोजिशन थी, वह पोजिशन जम्मू-कश्मीर की हो जानी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि डा. मनमोहन सिंह जी ने भी कहा कि pre-1953 position जम्मू-कश्मीर की वापस लाना उचित नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके कारण जम्मू-कश्मीर की जनता को 1953 के बाद जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन अधिकारों से वे वंचित हो जाएंगे। जम्मू-कश्मीर के हित में नहीं है कि pre-1953 position हो। लेकिन उसी समय जब कैबिनेट ने यह निर्णय किया कि pre-1953 position नहीं होगी तभी प्रधान मंत्री जी ने वहां की सरकार को कहा था, लेकिन हम तो कमिटिड हैं, जम्मू-कश्मीर के लिए नहीं, हिन्दुस्तान के सब राज्यों के लिए। हम यह मानते हैं कि over the years जो स्थिति पैदा हुई है, उसमें the Centre has become over-dominant, over-centralised. The structure has

become over-centralised. There is ample scope for devolution of powers in favour of States. There are States, like Jammu and Kashmir, which have very special history and very special aspirations. One can understand इसीलिए मैं बाकी सब के साथ नहीं जोड़ता हूं। बाकी सबका तो सरकारिया कमिशन के हिसाब से चल रहा है, इन्टर स्टेट काऊंसिल उस पर विचार कर रही है और उस पर कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन जम्मू और कश्मीर के बारे में अगर आप आइडेंटीफाई कर सकें कि अमुक-अमुक क्षेत्र में अगर मेरे अधिकार बढ़ाए जाएं और मुझे सेन्टर में न आना पड़े और मैं सीधे यहां पर निर्णय कर दूं तो हम उस पर विचार करने को तैयार हैं। यह बात चलती रही अनौपचारिक रूप से चलती रही और अभी पिछले दिनों में उसको औपचारिक रूप भी दिया गया है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि राम जेठमलानी जी ने बहुत सही कहा The dialogue should be sincere.अर्नेस्टनेस होनी चाहिए, प्रमाणिकता होनी चाहिए। इच्छा होनी चाहिए । हमारे स्वराज जी ने जो बातें कहीं, उनका मिजोरम का अनुभव है, अगर उस पर प्रमाणिक चर्चा होती है तो पिछले दिनों में बोडो के कुछ संगठनों के साथ हमारी बातचीत हुई है, एन.एस.सी.एन.(आई.एम.) के साथ हमारी जो बातचीत हुई है, उसमें हमने देखा है कि धीरे-धीरे करके, चाहे आरंभ में वे सोचते थे, हमारे बारे में एक धारणा थी बी.जे.पी. के लोग यूनिट्री स्टेट वाले हैं, ये फेडरलिज्म को मानते ही नहीं हैं इसलिए ये कुछ नहीं करेंगे लेकिन धीरे-धीरे इस सरकार ने सबके मन में एक विश्वास पैदा किया है कि हम जब कोई कदम उठाते हैं तो प्रमाणिकता से उठाते हैं । एन.एस.सी.एन.(आई.एम.) भी आज उसी नतीजे पर पहुंची है । बोड़ो, जो टेरेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन्स हैं, वे भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं । आज जम्मू-कश्मीर में अरुण जेटली जी ने जो चर्चा आरंभ की है, जो-जो लोग उनसे मिले हैं और जिन-जिन से उनकी बातचीत हुई है, उससे मुझे आशा है कि इस चर्चा में निश्चित रूप से अच्छे परिणाम निकलेंगे । मैं इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि यह बात प्रमाणिकता से होगी । हां, देश की एकता का हमेशा ध्यान रखा जाएगा, उसके बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता है । कल मुझे जेठमलानी जी से यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि जो लोग भारत के दुश्मन माने जाते थे, उनसे जब चर्चा की तो उस चर्चा के अंत में उन सबने भी यह माना कि भारत के संविधान के अंदर ही इस समस्या का हल निकालना संभव है । मुझे बहुत खुशी हुई । और इसीलिए नीलोत्पल जी, मैंने कहा कि आप भी इस दिशा में कुछ कोशिश करें तो मुझे खुशी होगी, मैं शिकायत नहीं करूंगा।

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): इनीशिएट से हमारी कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ठीक है, बहुत अच्छा है ।

श्री नीलोत्पल बसु : लेकिन उन्होंने पंजाब में भी पहले कुछ इनीशिएटिव लिया है । उसके बारे में शायद आप जानते हैं ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ट्रायफरकेशन का इतना जिक्र और करना चाहूंगा कि 51-52 से लेकर, मेरी पार्टी का उस समय जो काम था वह जम्मू तक सीमित था, वैली में नहीं था, लद्दाख में भी नहीं था । वहां पर मुझसे कई बार लोग मिलते थे, खासकर यूनिवर्सिटी के अध्यापक और दूसरे लोग भी मिलते थे, पूछते थे कि आपने हमें जम्मू-कश्मीर स्टेट के साथ क्यों नत्थी कर रखा है ? हम 370 को नहीं चाहते । हम तो चाहते हैं कि यह खत्म हो जाए । हम चाहते हैं कि हमारा भारत के साथ पूर्ण मर्जर हो जाए । अगर आप हमें स्टेट नहीं बनाना चाहते तो हम चाहते

हैं कि आप हमें हिमाचल के साथ मिला दीजिए लेकिन हमारे साथ यहां पर अन्याय हो रहा है । जम्मू-कश्मीर में जम्मू के लोगों से पूछिए, लद्दाख के लोगों से पूछिए, उन्हें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है । डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात होती है तो Devolution of power is there from New Delhi to Srinagar, from New Delhi to Kolkata, from New Delhi to Jaipur and from New Delhi to Shimla. हमें यह सोचना चाहिए कि the real devolution of power comes about only when there is devolution of power from New Delhi to Jaipur, Udaipur, Jodhpur, Ganga Nagar and to all other parts also. डेवेल्यूशन होना चाहिए और इसीलिए जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में डेवेल्यूशन की जो बात होगी, उस पर कल मनमोहन सिंह जी ने कहा, और भी कई लोगों ने जिक्र किया कि, मैं कई बार चुका हूं, बलराज पुरी से भी, उनके अपने विचार हैं, उनके अपने प्रपोजल्स हैं । उन प्रपोजल्स से हम सहमत हों या नहीं हों लेकिन मूलतः जम्मू और लद्दाख प्रदेश में उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए । बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए । यह एक अर्ज़ है । उस अर्ज़ में से यह बात निकलती है आप उस बेइंसाफी को दूर नहीं कर सकते, तो ठीक है, हम तो मांग करेंगे कि ट्राइफरकेशन हो । ट्राइफरकेशन कैसे होगा ? ट्राइफरकेशन होगा तो उसके इम्प्लिकेशन्स भी समझिए । इसके जो सबसे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण इम्प्लिकेशन्स हैं, वे ये हैं कि हमने 1947 में मजहब के आधार पर देश का बंटवारा मान लिया लेकिन इतिहास ही निर्णय करेगा कि यह सही था या गलत था, मैं नहीं जानता हूं । जनेश्वर जी ने एक बात कही । मैं जनेश्वर जी के नेता, जिनसे उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की है, डा. लोहिया को याद करता हूं । वे एक बार जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से मिले थे, 1954-55 की बात होगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उस समय भारतीय जनसंघ के नेता मात्र नहीं थे, हमारे मूल चिंतक थे He was our ideologue. हमने सार्वजनिक जीवन में विचारों, आचरण, व्यवहारों की सारी प्रेरणा उनसे प्राप्त की । डा. लोहिया ने उनसे कहा कि आपका राष्ट्रवाद मुझे बहुत पसंद है । लेकिन देश के मुसलमान आपके बारे में चिंतित इसलिए होते हैं क्योंकि आपने एक बार अखंड भारत की बात कह दी और उनको लगता है कि ये तो अखंड भारत की बात करते हैं और उनकी सरकार किसी दिन आ गयी तो ये हमला करके पाकिस्तान को भारत के साथ मिला देंगे। तब हमारी सरकार आने का कोई सवाल नहीं था। हम कोई हमला करके पाकिस्तान को मिला देंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। तब डा. लोहिया जी को दीनदयाल दयाल जी ने कहा कि मेरी कल्पना यह है अखंड भारत की कि एक दिन आएगा क्योंकि भारत का विभाजन इस आधार पर हुआ, उनके हिसाब से तो इस आधार पर हुआ कि ये दो अलग अलग राष्ट्र हैं, दो नेशन्स हैं अलग अलग, लेकिन भारत के नेताओं को, जिनको विभाजन स्वीकार नहीं था उन्होंने भी अगर माना तो इस कारण माना कि उनको लगा कि हम दोनों मिलकर रहेंगे तो ऐसे ही दंगे होते रहेंगे जेसे डायरेक्ट एक्शन के समय 1947 में हुए थे। इन दंगों से मुक्ति मिल जाएगी और एक बार दोनों देशों को अलग अलग मिल जाएगा - एक तरफ मुस्लिम लीग और एक तरफ कांग्रेस तो वे अपना अपना शासन चलाएंगे। देश का कुछ कार्य करेंगे, प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि उस समय जो दंगों का भय था, आज वह युद्ध का भय बन गया है। दंगों के भय की बजाए युद्ध का भय दोनों देशों के बीच हो गया है। तीन युद्ध पहले हो चुके हैं। चाहे ओवर्ट युद्ध नहीं है लेकिन युद्ध लगातार चल रहा है और इन तीन युद्धों में इतने लोग नहीं मरे जितने इन 30 सालों में लोग मरे हैं। इसलिए दीन दयाल उपाध्याय जी ने कहा कि मैं इस बात को मानता हूं कि यह विभाजन ठीक नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक दिन की कल्पना करता हूं जब दोनों देशों की जनता, दोनों देशों के नेता यह

पहचानेंगे कि इस विभाजन से किसी का भला नहीं हुआ - हमारा भी नहीं, उनका भी नहीं। कितना अच्छा हो कि दोनों देश मिलकर एक कन्फेडरेशन बनाएं। दोनों की सावरेनिटी बनी रहे, पाकिस्तान और भारत की सार्वभौमिकता बनी रहे लेकिन दोनों मिलकर एक कन्फेडरेशन बनाएं। जैसे ही उन्होंने यह कहा तो लोहिया जी ने उनको कहा कि यह तो बहुत अच्छा विचार है ...(**व्यवधान**)...

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Mr. Minister, are these your personal views or the views of the Government?..(*Interruptions*)..

THE DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Minister is speaking on behalf of the Government. So, there is nothing personal.

SHRI L.K. ADVANI: I am talking of 1955.और 1955 में उन्होंने कहा कि जब मैं अखंड भारत की बात करता हूं तो उसके बाद क्या हुआ - डा. लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक संयुक्त वक्तव्य निकाला कि जब जनसंघ के लोग अखंड भारत की बात करते हैं तो उनका अर्थ है, उनकी कल्पना है कि स्वेच्छा से एक महासंघ भारत और पाकिस्तान का बने। लेकिन उसके बाद तो बंगलादेश भी बन गया है और आज अगर कभी कोई महासंघ की बात करेगा - आप ही कर लें कोई बात नहीं, मैं क्यों करूं - तो मैं समझता हूं कि स्वाभाविक रूप से बंगलादेश के बारे में भी सोचना पड़ेगा, नेपाल को भी सोचना पड़ेगा, शायद बर्मा और श्रीलंका को भी सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब उन्होंने कहा था - दीनदयाल जी ने और लोहिया जी ने - तो कई लोगों ने कहा था कि सर्वथा अव्यवहारिक है It is impossible. This cannot happen. How can it happen? It is absurd.

इस साल नहीं पिछले साल सन् 2001 में मैं जर्मनी गया और मैं जर्मनी 25 साल के बाद गया। 25 साल पहले गया था जब सूचना और प्रसारण मंत्री था। मोरारजी भाई की सरकार थी तब जाने का मौका मिला था और ईस्ट जर्मनी ने आई एण्ड बी मिनिस्टर के नाते बुलाया था। वहां पर मेरा सारा दौरा ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी : महोदया ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : रिलेटेड है ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी : ये कोई पार्टी वर्कर्स को सम्बोधित नहीं कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : नहीं नहीं, वे बता रहे हैं, सुनिए तो ...(**व्यवधान**)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं नहीं बताऊंगा ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... I will not permit any interruptions...(*Interruptions*).. Please sit down...(*Interruptions*).. Everbody has spoken about history...(Interruptions)... अबरार अहमद साहब, आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... वे बोल रहे हैं। कल एनसी के मेम्बर ने हिस्टोरिकल बात बोली थी तो किसी ने ऐतराज नहीं किया। हिस्ट्री की वजह से ही हालात बनते हैं.. Let him reply...(*Interruptions*)...

एक माननीय सदस्य : जनेश्वर जी ने कन्फेडरेशन के बारे में पूछा है ...(**व्यवधान**)...
श्री नीलोत्पल बसु : बोलने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ...(**व्यवधान**)...

SHRI L.K. ADVANI: I am concluding...(*Interruptions*)..

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him reply.....*Interruptions*)..

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। कोई जरूरी नहीं है। जनेश्वर जी ने क्योंकि कन्फेडरेशन की बात पूछी थी मुझसे इसीलिए कहा ...(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्र : जब बर्लिन की दीवार टूट सकती है तो यह क्यों नहीं ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, ठीक बात है । ...(**व्यवधान**)...

आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगा और वह यह है कि क्रॉस बॉर्डर टैररिज्म, उसका अर्थ केवल इनफिल्ट्रेशन है । उसका अर्थ है, "essentially, the infrastructure for infiltration of terrorism that has been built up by our neighbour, that has to be dismantled." वह डिसमेंटल होना चाहिए और नीति के नाते टैररिज्म को अपनाने का उन्होंने जो निर्णय किया हुआ है 1971 के बाद उसका उनको परित्याग करना चाहिए । जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में उनको मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि अनेक बार वह सैल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, एक बार मुझे अवसर आया और उस समय प्रधान मंत्री श्री नरसिंहै राव थे, मुझे उन्होंने स्ट्रैसबर्ग में होने वाली कांफ्रेंस में भेजा और कहा कि पाकिस्तान वहां पर जम्मू-कश्मीर के सवाल को उठाएगा, इसलिए आप वहां पर जवाब दें तो अच्छा होगा । मैं वहां पर गया था और वहां पर उन्होंने सवाल उठाया था और कहा था कि कई सारे देश हैं जो सैल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार को और सप्रैस करते हैं बाय मिलिट्री फोर्स और उनका अभिप्राय जम्मू-कश्मीर से था । मैंने जवाब देते हुए उनको कहा था कि भारत जो है, it is a multi-lingual country; it is a multi-religious country; it is a multi-ethnic country. To some extent, Pakistan is also similar, except that it is not a multi-religious country. और हम 50 साल से कोशिश् करते रहे हैं to develop it into a single viable State, and we have succeeded in it. We have succeeded in making it a single viable nation-State. I do not know whether you have succeeded or not. हम इस बात के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं कि सैल्फ डिटर्मिनेशन के नाम पर कोई सशैसनिज्म न फैलाए । Perhaps you do not know that I belong to Sindh, and that the right of self-determination were given to the people of Sindh. At that point of time, the movement in Sindh was very powerful. You do not know what the consequences would be in Sindh and Baluchistan. You do not realise that. और उन्होंने कहा कि Jammu & Kashmir is not merely an issue between India and Pakistan. It is an issue of a wider nature. It is related to the unity of this country. It is related to the adoption of secularism by our country. और आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी और उसके बाद सिंध के जितने सारे उसमें प्रतिनिधि थे उन्होंने आकर मुझे कहा कि बहुत अच्छा आपने सुनाया है उनको, बहुत ठीक किया। लेकिन मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वेस्टर्नर्ज़ कभी-कभी इस बात को नहीं पहचान पाते कि

जम्मू-कश्मीर उससे भी जुड़ा हुआ है और इसीलिए मैं दुनिया के देशों को भी कहना चाहूंगा कि इस मामले में हम भारत सरकार की ओर से प्रामाणिकता से चर्चा करके जो भी उचित होगा हम जम्मू-कश्मीर में करेंगे । उसमें विदेशियों का कोई स्थान नहीं है । वहां पर प्रामाणिकता से, ईमानदारी से इलैक्शन हों, इसका भी प्रबन्ध करेंगे, वहां पर डिवेलपमेंट हो इसका भी प्रबन्ध करेंगे, डेवोल्यूशन हो इसका भी प्रबन्ध करेंगे । लेकिन जो भी करेंगे we will regard it as an internal problem of India. हां, अगर कोई इंटरनेशनल उसका आयाम है तो हमारे पड़ौसी का क्रॉस बॉर्डर टैररिज्म उसमें जितनी सहायता विदेशी कर सकें, जरूर करें, हम उसका स्वागत करेंगे । मुझे और कुछ नहीं कहना है । ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, there is no time. We will have to take up the Calling Attention Motion on the matter of urgent public importance. ...(*Interruptions*)... No; nothing would be allowed once the reply is over.

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदया ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : देखिए, गुलाम नबी जी, इस चर्चा के लिए केवल 4 घंटे रखे गए थे, जबकि 5 घंटे और 45 मिनट यहां चर्चा हुई, रिप्लायी को छोड़ने के बाद । अभी कालिंग अटेंशन है। वह भी इंपार्टेंट हैं । मंत्री जी बैठे हैं । ...(**व्यवधान**)... Now, I will have to call the attention of the Minister to the matter of urgent public importance.

श्री अर्जुन सिंह (मध्य प्रदेश): महोदया, मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं ।

उपसभापति : देखिए, अगर आप सवाल पूछेंगे तो दस लोग और पूछेंगे । फिर से एक नई चर्चा तो शुरु नहीं कर सकते । ...(**व्यवधान**)... We went against the rules to allow the reply ...(*Interruptions*)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Madam, it is a matter of serious nature. ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not need your support. (*Interruptions*)... Mr. Poojary, please sit down. Please take your seat. ...(*Interruptions*)... Please take your seat. You had been a Minister, Mr. Poojary. Kindly take your seat.

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान): पाकिस्तान का हाथ है, कहकर आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

उपसभापति : आप बैठिए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up the Calling Attention.

SHRI ARJUN SINGH: Madam, this is also a matter of urgent public importance.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is why I have allowed.

SHRI GHULAM NABI AZAD: And see that is the reply.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up the Calling Attention. Mr. Dipankar Mukherjee.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Issues arising out of decision of VSNL Board to invest Rs. 1200 crores in Tata Tele Services Ltd.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Madam, I beg to call the attention of the Minister of Communications and Information Technology on the issues arising out of the decision of the VSNL Board to invest Rs.1200 crores in TATA Tele Services Ltd.

[The Vice-Chairman, Shri Suresh Pachouri, in the Chair.]

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, the Government has disinvested 25 per cent Government equity in Videsh Sanchar Nigam Ltd. to a strategic partner, M/s. Panatone Finvest Limited through due disinvestment process. The Share Purchase Agreement (SPA) was signed on 6th February, 2002 and the Share Holder Agreement (SHA) was signed on 13th February 2002. The strategic partner paid the consideration on 13th February, 2002 and took over the management control of VSNL.

A notice for convening the 127th meeting of the Board of Directors of VSNL for 28th May, 2002 was received on 21st May, 2002. Agenda for the meeting included an agenda item B.11 "to consider inter-corporate investment up to Rs.1200 crore in the equity of an Indian company holding Basic Service Operator (BSO) license." No details about the targeted company were given in the agenda item.

The Board meeting was attended by one of the two Government nominee Directors, namely Shri Rakesh Kumar, Sr. DDG (SU), Department of Telecommunications. Shri Y.S. Bhave, Joint Secretary, Department of Information and Technology, the other Government nominee Director could not attend the meeting as he was on tour abroad.

The Government Director, Shri Rakesh Kumar, has informed that during the meeting, a presentation was made by Director (Operations) of VSNL, giving justification for the need for making such an inter-corporate investment without mentioning the targeted company. The Government